प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
DEPARTMENT OF
ADMINISTRATIVE REFORMS &
PUBLIC GRIEVANCES
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

सचिवालय सुधार

क) निर्णय लेने में दक्षता वृद्धि
ख) ई-ऑफिस
ग) स्वच्छता अभियान और लंबित मामलों में कमी

मासिक रिपोर्ट | मई 2025

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

विषय सूची

1. मुख्य मुख्य बातें 5
I. ई-ऑफिस एनालिटिक्स और कार्यान्वयन 5
II. स्वच्छता अभियान की उपलब्धियां (मई 2025)..... 6
III. लंबित मामलों को घटाना.....6
2. सुशासन प्रथाओं का अनुकरण: राज्य स्तरीय उपलब्धियां 7
3. स्वच्छता पखवाड़ा 2025: सु-शासन के प्रति डीएआरपीजी की निरंतर प्रतिबद्धता 8
4. औसत विशिष्ट स्तरों के अनुसार मंत्रालयों/विभागों का वितरण (डिलेयरिंग)..... 9
4.1 डिलेयरिंग प्रवृत्ति (मई 2025).....9
4.2. डिलेयरिंग की स्थिति (मई - 2025).....10
क. ऐसे मंत्रालय/विभाग जिनका औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर ≤ 4 तक है 10
ख. ऐसे मंत्रालय/विभाग जिनका औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर 4 से अधिक तथा 5 से कम या बराबर हो.....10
ग. 5 से अधिक औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर वाले मंत्रालय/विभाग.....11
5. ई-ऑफिस एनालिटिक्स और कार्यान्वयन 12
5.1 ई-ऑफिस एनालिटिक्स.....12
5.2 ग्रोथ ऑफ ई-फाइल्स.....13
5.3. ई-फाइल बनाना (मई 2025).....14
5.4. अंतर-विभागीय फ़ाइल संचलन.....14
5.5. ई-रिसीट अपनाना (ई-रिसीट का शेयर %).....15
5.6. ई-ऑफिस एनालिटिक्स.....16
6. विशेष अभियान और स्वच्छता को संस्थागत करना 20
6.1. कुल अर्जित राजस्व (करोड़ रुपए में).....20
6.2 स्क्रैप निपटान से अर्जित राजस्व (मई 2025) 21
6.3. खाली हुआ स्थान (मई 2025) 21
क. शीर्ष 3 मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्क्रैप निपटान के माध्यम से अर्जित राजस्व.....22
6.4. स्वच्छता अभियान साइट (मई 2025).....23
6.5. छाँटी गई फिजिकल फाइलें (मई 2025).....23
7. पहले - बाद में 24
8. श्रेष्ठ परिपाटियां ई-कचरा निपटान 25
9. मंत्रालयों/विभागों का मापदंड - वार कार्य निष्पादन.....26
10. इन फोकस: कोयला मंत्रालय.....28
क.परिचय.....28
ख.झलक.....28

स्वच्छता.....28
स्थान का कुशल प्रबंधन.....29
कार्यालय स्थल का संवर्धन.....30
अपशिष्ट से धन.....31
11. निर्णयन में दक्षता वृद्धि पर कार्यालय ज्ञापन 32
12. स्वच्छता को संस्थागत करने पर कार्यालय ज्ञापन.....33
13. ई ऑफिस पर कार्यालय ज्ञापन.....35
अनुलग्नक I : अपलोड न किए गए आंकड़े 37
अनुलग्नक II- संक्षिप्ताक्षरों की सूची.....38

1 मुख्य- मुख्य बातें मई- 2025

I. ई-ऑफिस एनालिटिक्स और कार्यान्वयन

40

मंत्रालयों/विभागों के पास 100% ई-फाइलें है

15

मंत्रालयों/विभागों के पास 100% ई-रिसीट्स है।

21

ऐसे मंत्रालय/विभाग जिनका औसत ट्रांजैकशन स्तर 4 से कम या बराबर है

ई-फाइल उपयोग (%)

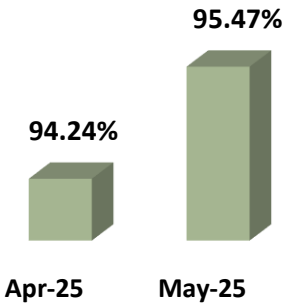

मई 2025: 5,29,070 रिसीट्स में से 5,02,606 ई- रिसीट्स थीं

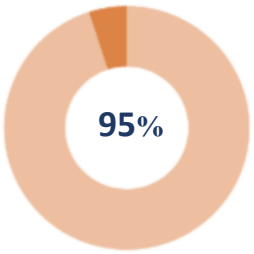

औसत ट्रांजैकशन स्तर

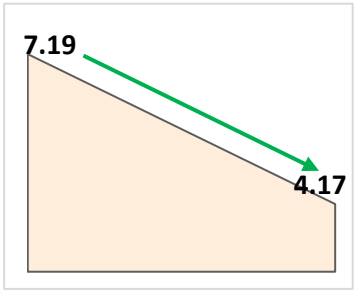

सक्रिय, बंद और कुल ई-फाइल्स के मासिक आंकड़े

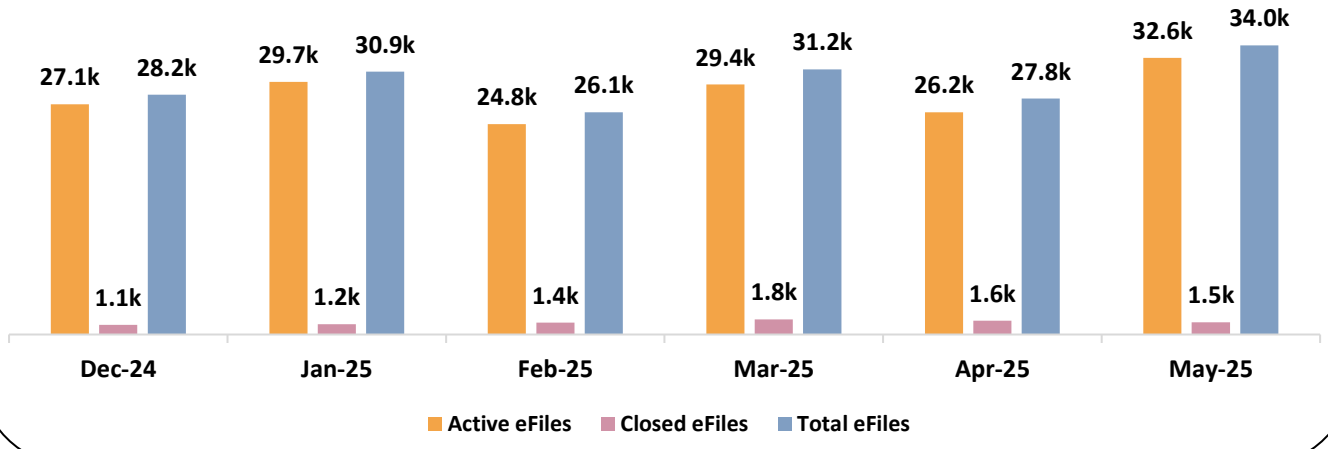

II. स्वच्छता अभियान की उपलब्धियां (मई 2025)

8,835
स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया

3,45,897
वर्ग फीट खाली हुआ स्थान

2,84,84,39,141
स्क्रैप निपटान से अर्जित राजस्व

III. लंबित मामलों को घटाना

निपटान

4,57,081 लोक शिकायतें

19,613 लोक शिकायत अपील

1,448 संसद सदस्यों से संदर्भ

320 राज्य सरकारों से संदर्भ

85 आईएमसी संदर्भ

356 पीएमओ संदर्भ

पूरे किए गए संसदीय आश्वासन

57

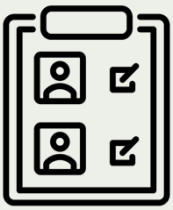

अभिलेख प्रबंधन

1,04,941 फिजिकल फाइलों की समीक्षा की गई और 66,186 फिजिकल फाइलों की छँटाई ।

2 सुशासन प्रथाओं का अनुकरण: राज्य स्तरीय उपलब्धियां

पृष्ठभूमि और उपलब्धियां

केंद्रीय स्तर पर किए गए सचिवालय सुधारों को अब महाराष्ट्र और हरियाणा द्वारा सक्रिय रूप से दोहराया जा रहा है, जो केंद्रीय सचिवालय की सीमाओं से परे इन पहलों के बढ़ते प्रभाव और प्रासंगिकता को दर्शाता है। पटना में 29 अप्रैल 2025 को लॉन्च किया गया स्वच्छ बिहार पोर्टल, केंद्रीय पहलों के राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन में सफल ट्रांजिशन का नवीनतम उदाहरण है। एससीडीपीएम पोर्टल (लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान) की सबसे करीबी राज्य-विशिष्ट प्रतिकृति के रूप में डिज़ाइन किया गया, इसे एनआईसी की डीएआरपीजी तकनीकी टीम के सपोर्ट से बिहार के प्रशासनिक संदर्भ के अनुरूप बनाया गया है। यह पोर्टल बिहार में विभागों में स्वच्छता, शिकायत निवारण और डिजिटल फ़ाइल प्रबंधन की संरचित निगरानी को सक्षम बनाता है, जिससे जमीनी स्तर पर सुशासन प्रथाओं को संस्थागत बनाया जा सके।

स्वच्छ पोर्टल की मुख्य कार्यक्षमताएं

अभिलेख प्रबंधन

स्वच्छता अभियान की रिपोर्टिंग

स्क्रैप निपटान ट्रैकिंग

एकीकृत निगरानी डैशबोर्ड

केंद्र-राज्य प्रतिकृति

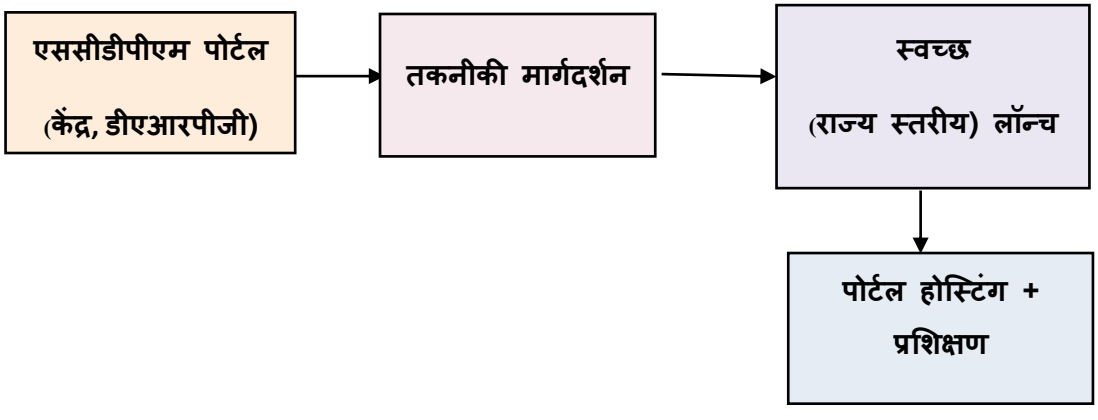

मीडिया कवरेज

वाड़ी हेल्थ सोसाइटी द्वारा फाइब्रो स्कैन जांच शिविर आयोजित

राज्य में शुरू हुआ 'स्वच्छ बिहार' पोर्टल

मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने किया लॉन्च

महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने विभाग के साथ की समीक्षा बैठक

3 स्वच्छता पखवाड़ा 2025: सु-शासन के प्रति डीएआरपीजी की निरंतर प्रतिबद्धता

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने 16-31 मई, 2025 तक स्वच्छता पखवाड़ा 2025 मनाया। पेयजल और स्वच्छता विभाग के तत्वावधान में समन्वित यह वार्षिक पहल स्वच्छता, जन भागीदारी और सार्वजनिक स्वच्छता और हरित जीवन के गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

प्रमुख गतिविधियां

पहल	विवरण
स्वच्छता शपथ	वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा डीएआरपीजी के समर्पण की पुष्टि करने के लिए सामूहिक शपथ
श्रमदान गतिविधियाँ	आस-पास के इलाकों में स्वच्छता अभियान चलाए गए और स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा आयोजित की गई
वृक्षारोपण अभियान	शहरी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हरित पहल

अभियान की झलकियाँ

4 औसत विशिष्ट स्तरों के अनुसार मंत्रालयों/विभागों का वितरण (डिलेयरिंग)

मुख्य व्याख्या

केंद्रीय सचिवालय में सक्रिय फाइलों के लिए औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन लेवल 2021 में 7.19 से घटकर मई 2025 में केवल 4.17 रह गया है, जिससे प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित होंगी और दक्षता बढ़ेगी।

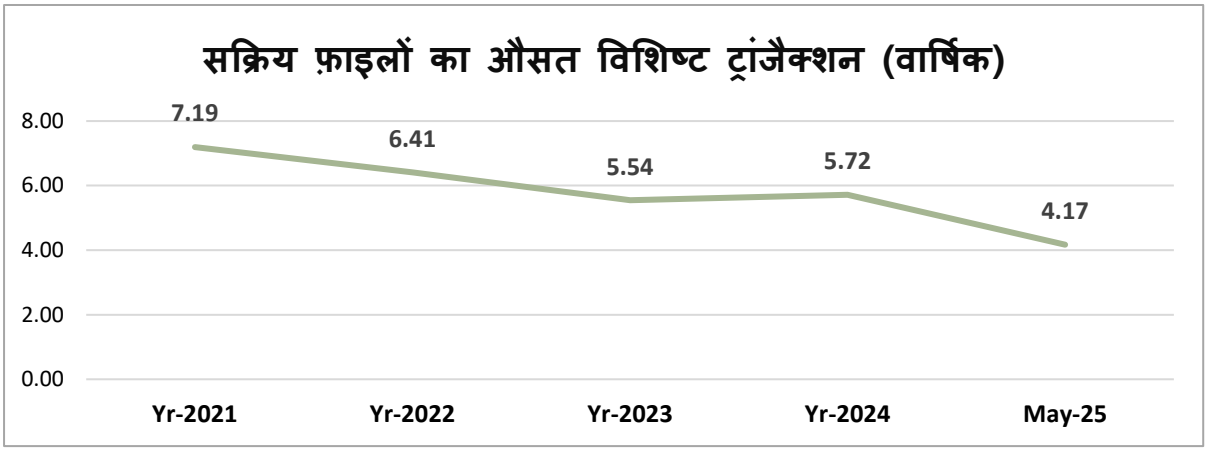

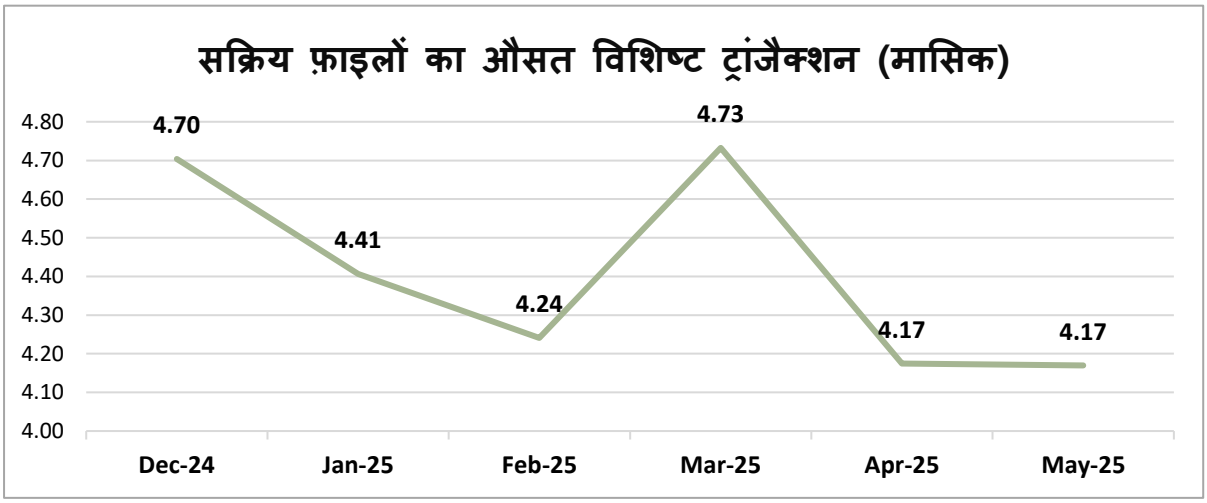

4.1 डिलेयरिंग प्रवृत्ति (मई 2025)

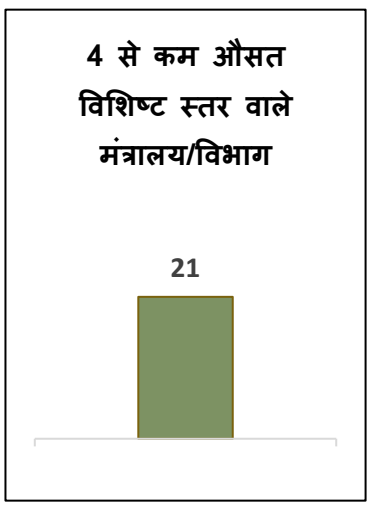

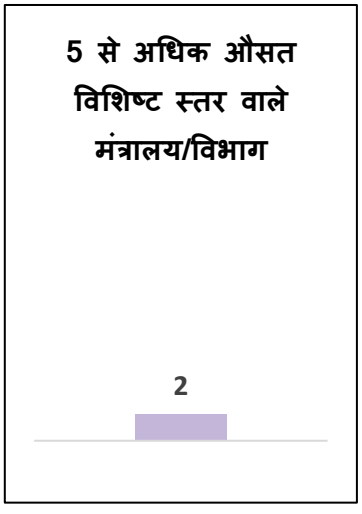

4.2 डिलेयरिंग की स्थिति (मई - 2025)

निम्नलिखित ग्राफ मई, 2025 के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तरों को दर्शाता है:

क. ऐसे मंत्रालय/विभाग जिनका औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर ≤ 4 तक है

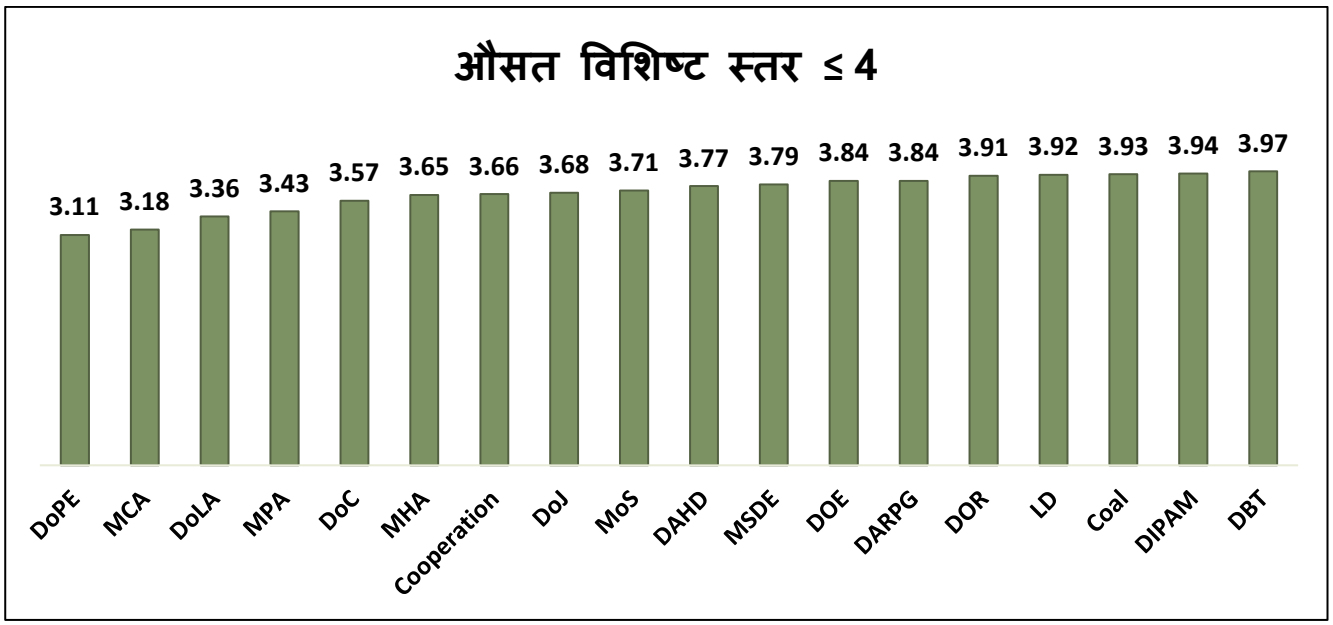

ख. ऐसे मंत्रालय/विभाग जिनका औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर 4 से अधिक तथा 5 से कम या बराबर हो

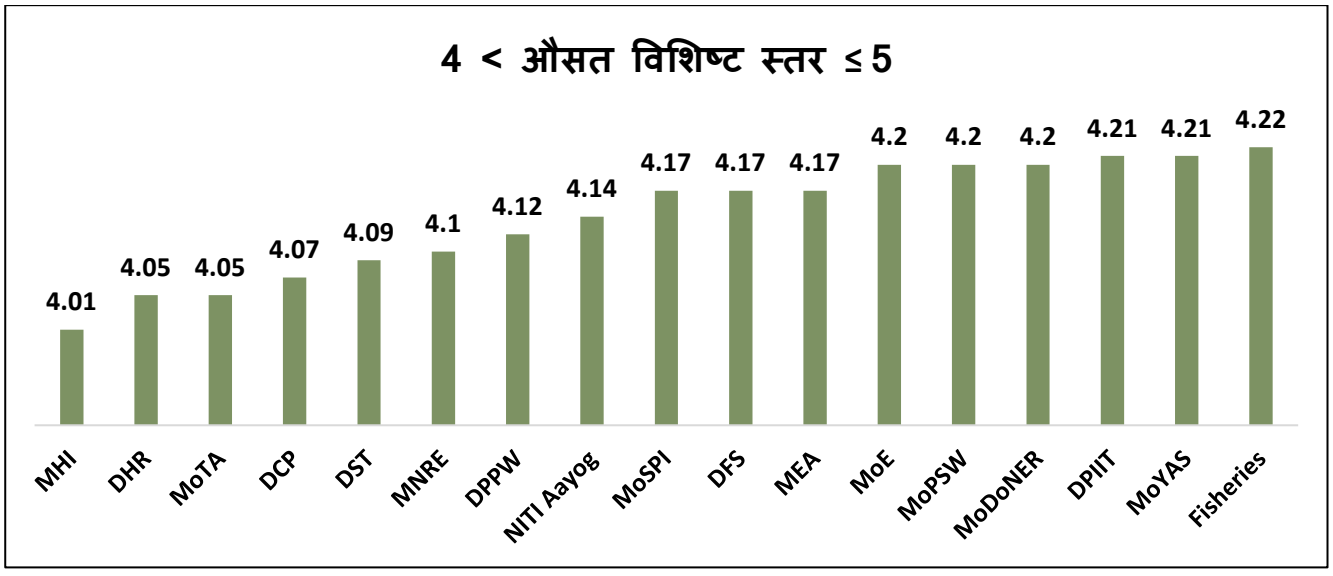

- **औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर >4 और ≤ 5 वाले मंत्रालय/विभाग (जारी)**

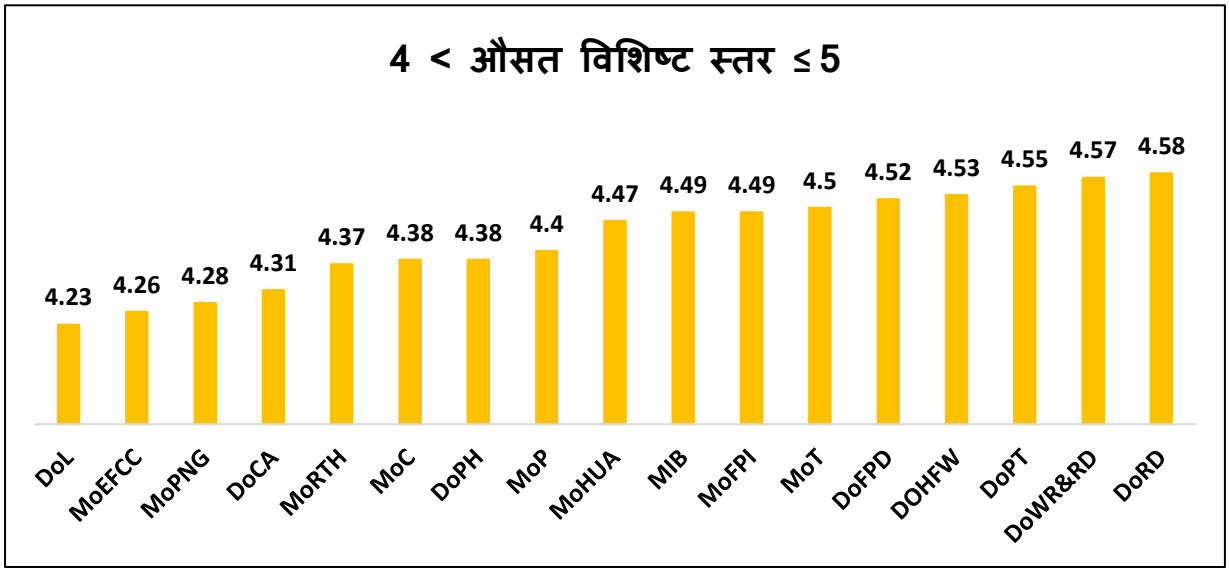

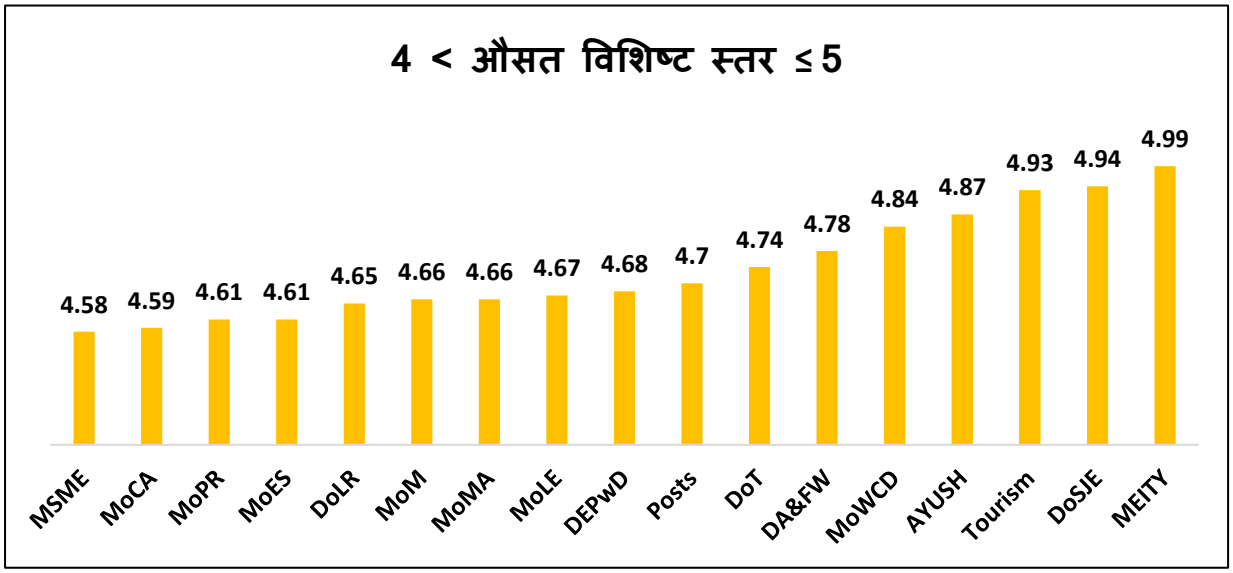

ग. 5 से अधिक औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर वाले मंत्रालय/विभाग

केवल **दो** मंत्रालयों/विभागों का औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर 5 से अधिक है - **उर्वरक विभाग (डीओएफ) का 5.01** और **पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (एमओडीडब्ल्यूएस)** का **5.39** ।

5 ई-ऑफिस एनालिटिक्स और कार्यान्वयन

5.1 ई-ऑफिस एनालिटिक्स

- ई-ऑफिस एनालिटिक्स डैशबोर्ड (https://vishleshan.eoffice.gov.in/) का शुभारम्भ दिनांक 19 दिसंबर, 2023 को किया गया।

यह डैशबोर्ड निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है:

- गहन डेटा विश्लेषण को आसान बनाने और निर्णयन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए रियल टाइम मेट्रिक्स
- डेटा और ट्रेंड के विज़ुअलाइज़ेशन के माध्यम से निर्णयन को प्रोयोक्तानुकूल बनाना
- ई-ऑफिस को और अधिक सुव्यवस्थित एवं मजबूत बनाने के लिए डेटा विश्लेषण
- आईईडीएम के व्यापक कार्यान्वयन को सुगम बनाना।

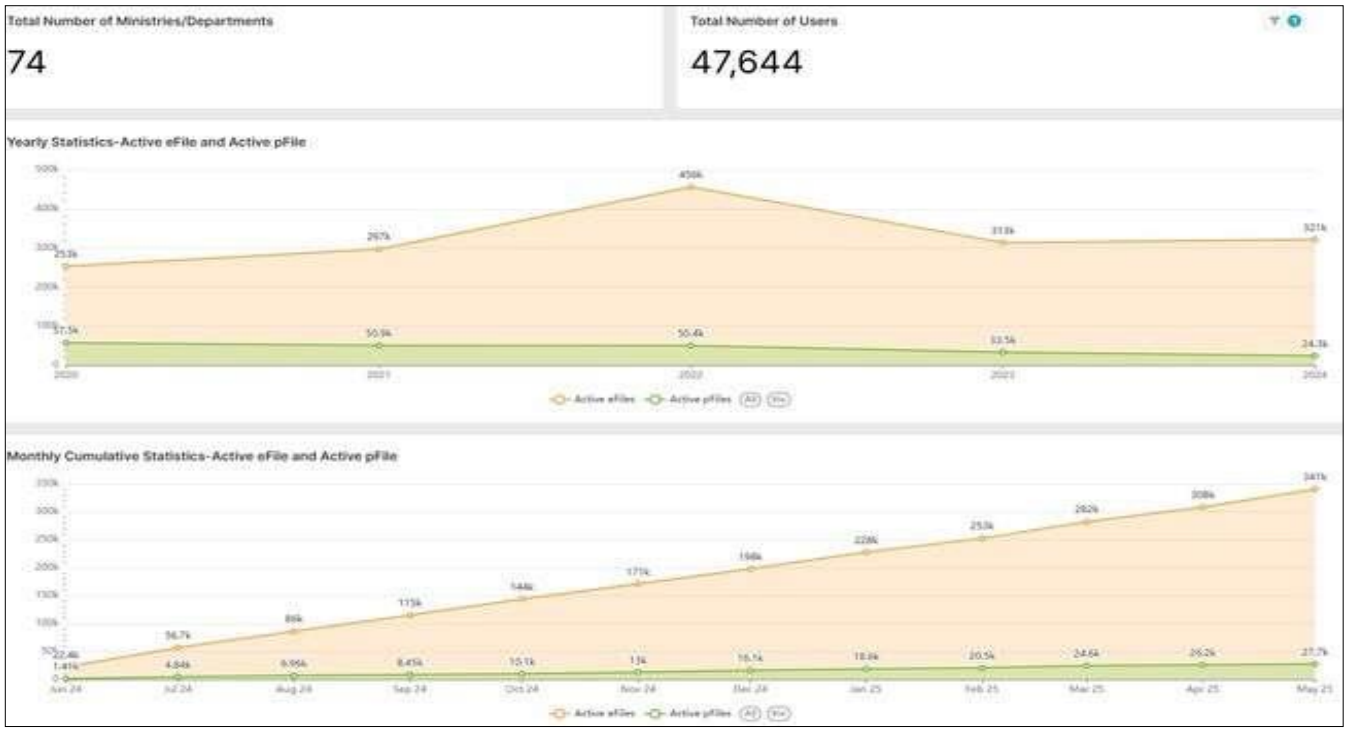

ईऑफिस एनालिटिक्स डैशबोर्ड इंटरफ़ेस
यूआरएल:https://vishleshan.eoffice.g

डैशबोर्ड केवल एनआईसी नेट पर उपलब्ध है। वर्तमान में, यह भारत सरकार के सभी सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों (केवल एनआईसी ईमेल) और मोबाइल नंबर के विवरण के साथ एनआईसी से विशिष्ट अनुरोध किया जाना है) के लिए सुलभ है।

5.2 ग्रोथ ऑफ ई-फाइल्स

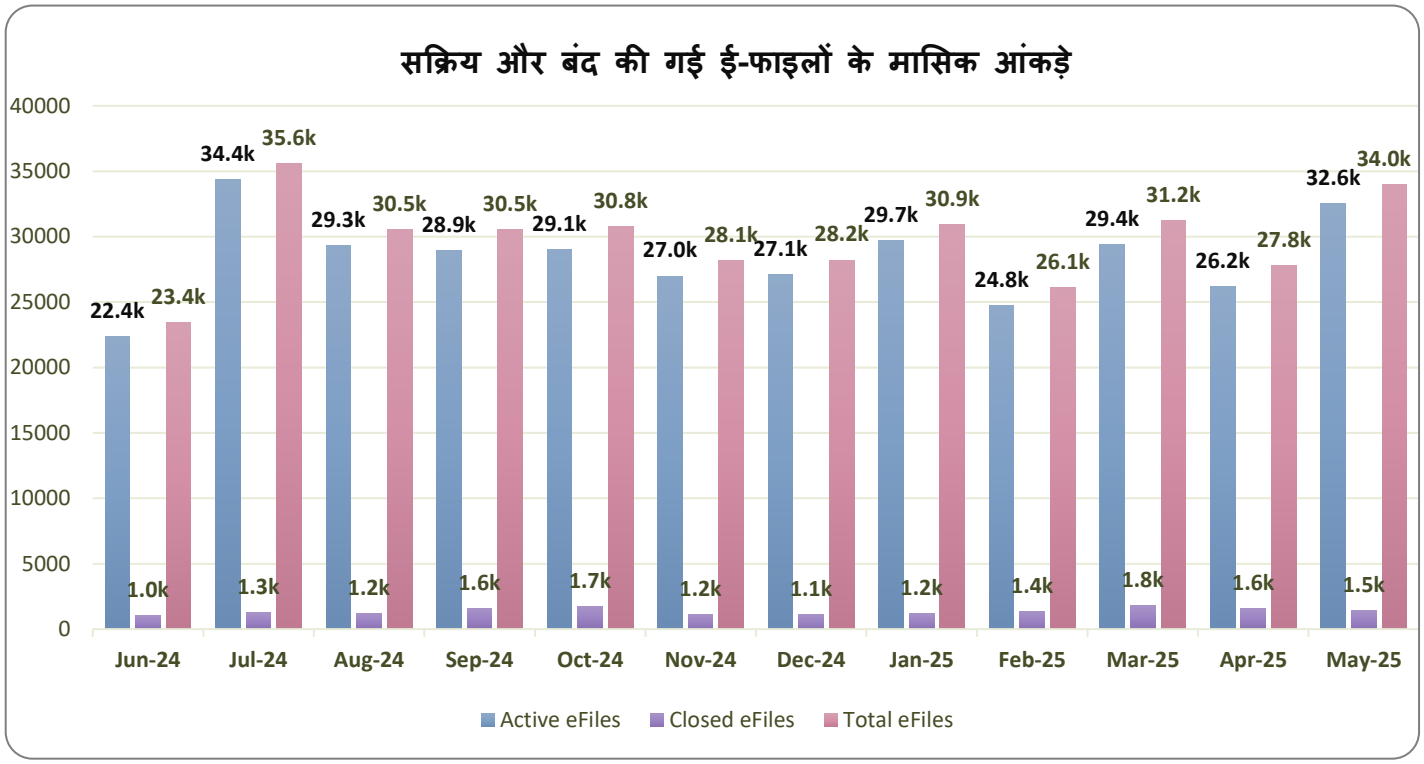

जून, 2024 से मई 2025 तक ई-फाइलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, **जो मई 2025 में 34.0** हजार हो गई है। यह मंत्रालयों/विभागों में ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म के निरंतर अपनाए जाने और सक्रिय उपयोग को दर्शाता है , जिसमें सक्रिय और बंद की गई फाइलों को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है - जो ***बेहतर डिजिटल वर्कफ़्लो और फ़ाइल प्रबंधन को दर्शाता है।***

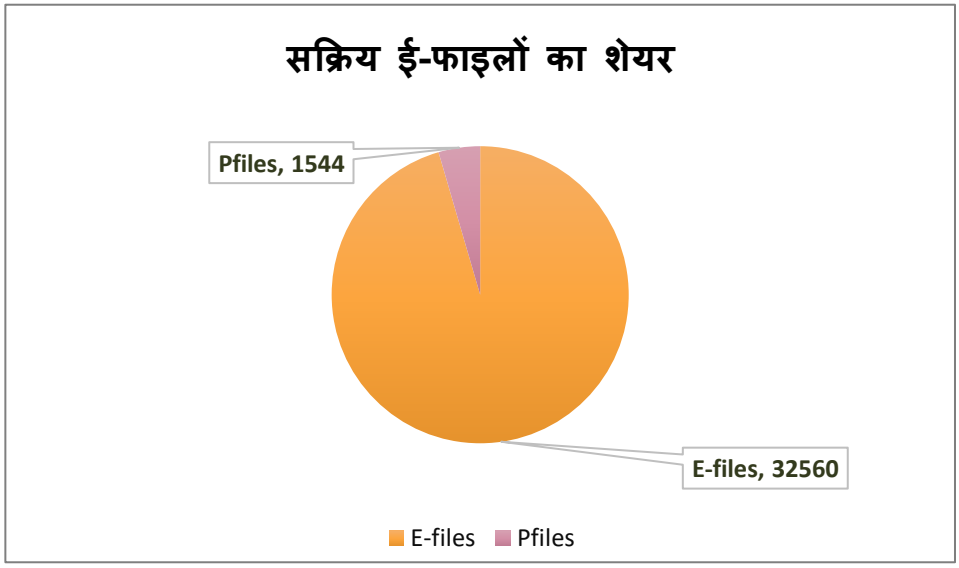

मई 2025 में कुल सक्रिय फाइलों में ई-फाइलों का शेयर 95.47% था, जो फिजिकल फाइलों की तुलना में डिजिटल फाइलों के प्रमुख उपयोग को दर्शाता है।

5.3. ई-फाइल बनाना (मई 2025)

मई 2025 माह के लिए सक्रिय ई-फाइलों में <90% शेयर वाले मंत्रालय/विभाग :

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	ई-फाइल्स का % शेयर
1	दूरसंचार विभाग	89.23%
2	व्यय विभाग - वित्त मंत्रालय	88.93%
3	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	86.95%
4	गृह मंत्रालय	69.27%
5	राजभाषा विभाग	6.98%

5.4. अंतर-विभागीय फ़ाइल संचलन

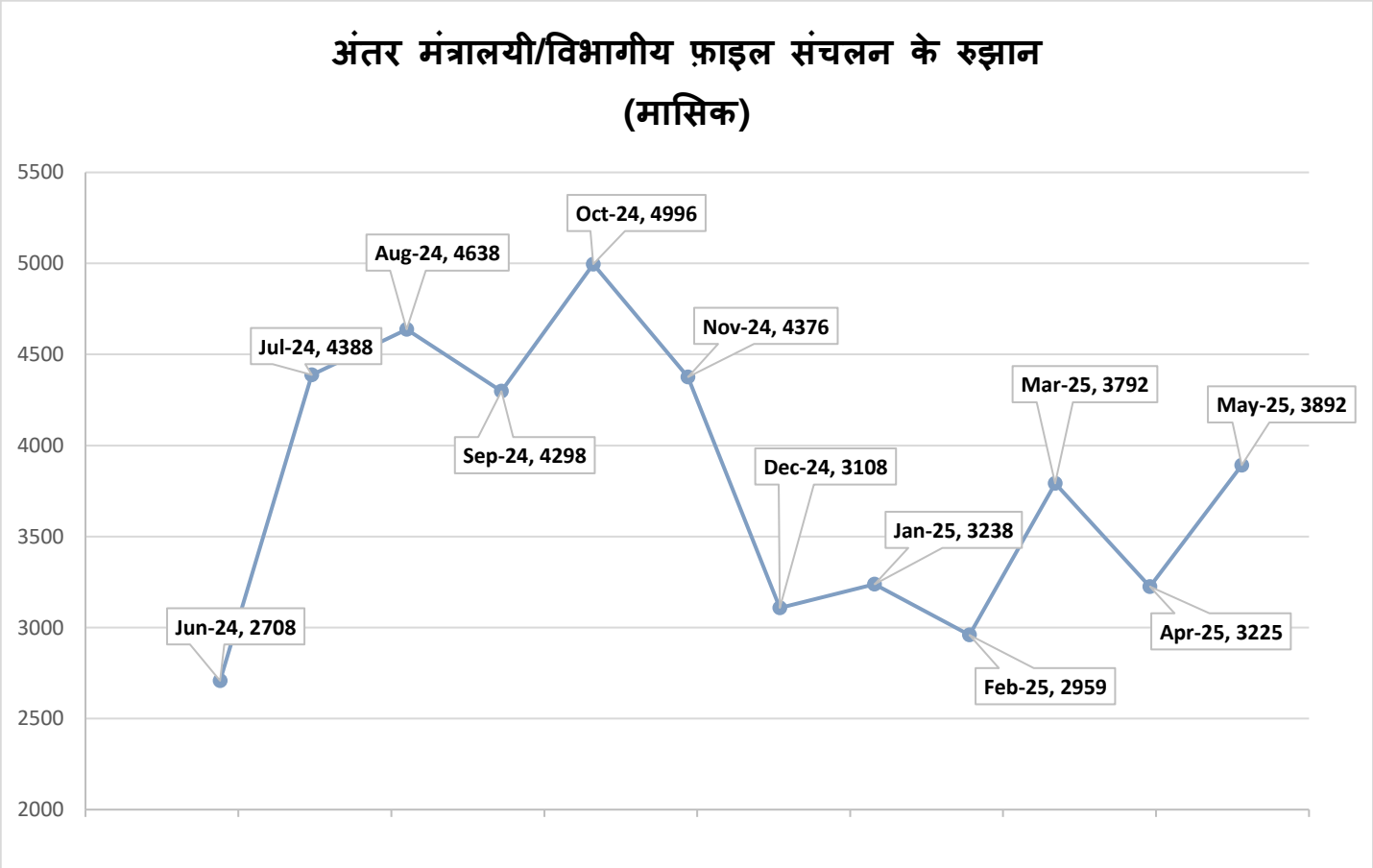

- **अंतर-मंत्रालयी फ़ाइल संचलन में अग्रणी मंत्रालय/विभाग – मई 2025**

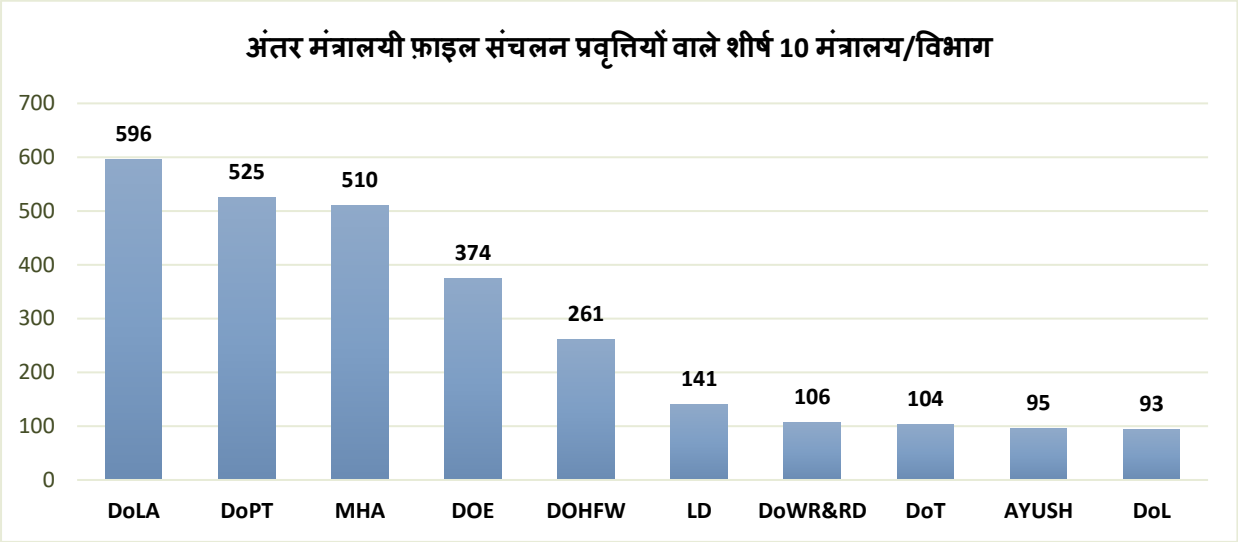

मई 2025 माह के लिए **विधि कार्य विभाग के** पास अंतर-मंत्रालयी फाइलों की अधिकतम संख्या (**596**) है, जिसके बाद **कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग** (**525**) और **गृह मंत्रालय** (**510**) **का स्थान है** ।

5.5. ई-रिसीट अपनाना (ई-रिसीट का शेयर %)

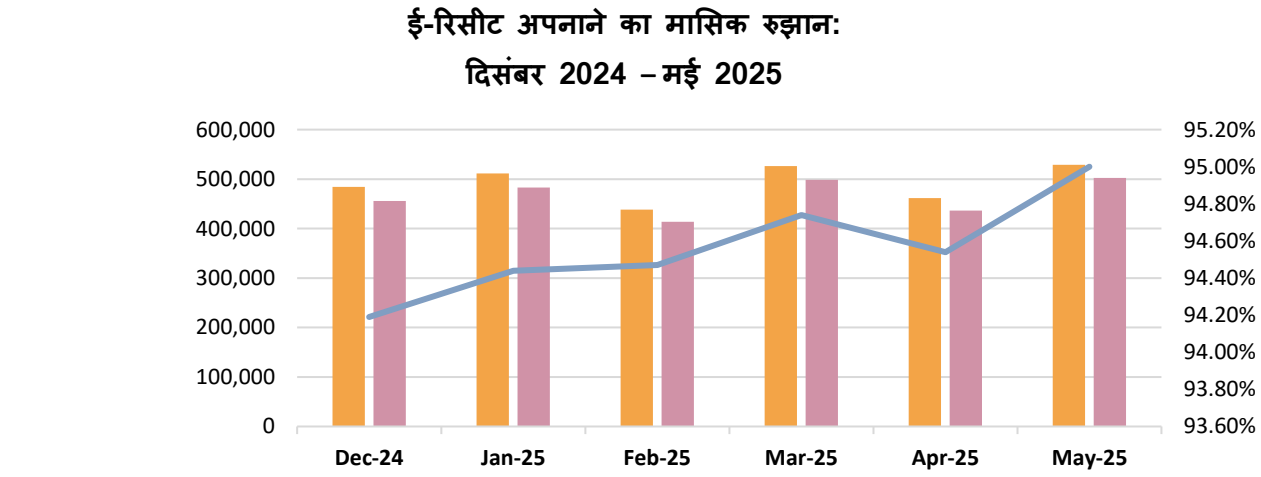

	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25
Total Receipts Received	484,051	511,636	438,248	526,379	461,603	529,070
Total eReceipts Received	455,915	483,198	414,013	498,672	436,387	502,606
%age eReceipt	94.19%	94.44%	94.47%	94.74%	94.54%	95.00%

पिछले छह महीनों में ई-रिसीट्स का शेयर लगातार 94% से ऊपर बना हुआ है , जो **मई 2025 में 95% के उच्चतम स्तर पर है** – यह मंत्रालयों/विभागों में रिसीट प्रबंधन में पर्याप्त डिजिटल अडॉप्शन का संकेत है।

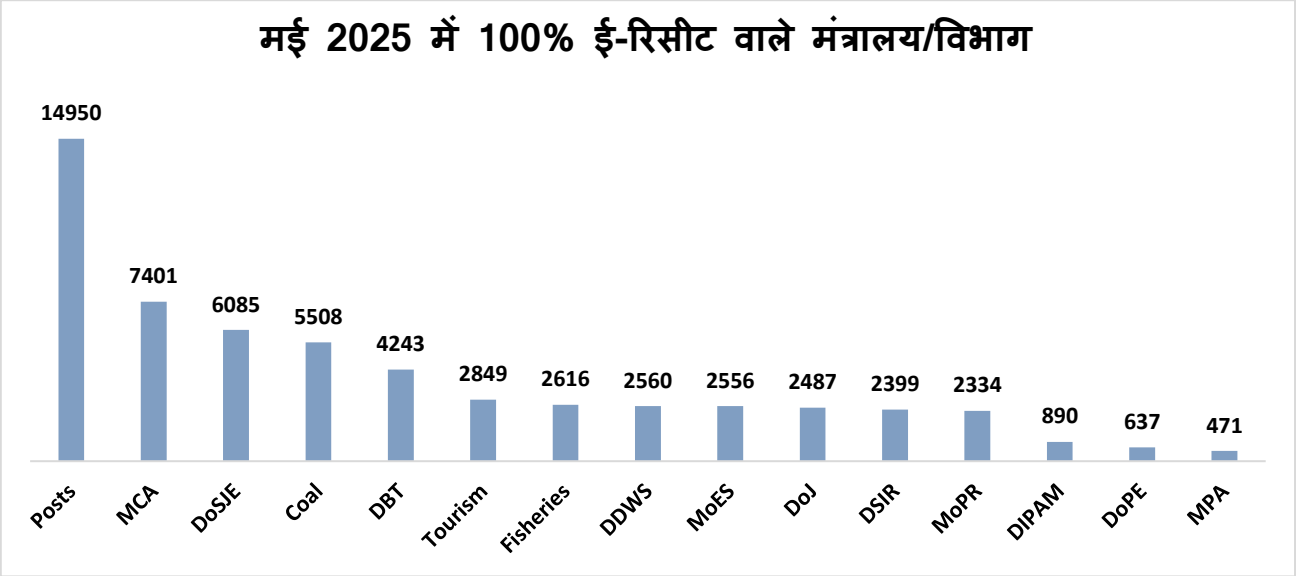

मई 2025 तक **15** मंत्रालयों/विभागों के पास **100% ई-रिसीट्स हैं, जिसमें डाक विभाग 14,950 ई-रिसीट्स** के साथ अग्रणी है , इसके बाद **एमसीए** (**7,401**) और **डीओएसजेई** (**6,085**) **हैं** - जो अनुकरणीय डिजिटल रिसीट कार्रवाई को दर्शाता हैं।

5.6. ई-ऑफिस एनालिटिक्स

मई 2025 के लिए मंत्रालय-वार विश्लेषण का सारांश इस प्रकार है:

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	% सक्रिय ई-फाइलें	% ई-रिसीट	>4 औसत विशिष्ट स्तर वाली फ़ाइलों का %
1	डीईए - वित्त मंत्रालय	99.92%	96.36%	5.70%
2	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	99.87%	97.99%	38.91%
3	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	100.00%	98.34%	33.33%
4	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	100.00%	98.77%	-
5	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	97.23%	99.58%	50%
6	पशुपालन और डेयरी विभाग	99.74%	99.87%	26.10%
7	बायोटेक्नोलॉजी विभाग	100.00%	100.00%	28.36%
8	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	100.00%	99.84%	37.33%
9	वाणिज्य कर विभाग	99.89%	96.68%	27.58%

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	% सक्रिय ई-फाइलें	% ई-रिसीट	>4 औसत विशिष्ट स्तर वाली फ़ाइलों का %
10	उपभोक्ता मामले विभाग	100.00%	99.98%	38.13%
11	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	100.00%	100.00%	62.10%
12	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	100.00%	99.85%	43.06%
13	उर्वरक विभाग	100.00%	99.28%	49.28%
14	मत्स्य विभाग	100.00%	100.00%	34.33%
15	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	100.00%	99.67%	40.26%
16	न्याय विभाग	98.28%	100.00%	24%
17	भूमि संसाधन विभाग	100.00%	99.92%	56.14%
18	विधि कार्य विभाग	100.00%	99.99%	11.03%
19	राजभाषा विभाग	6.98%	26.90%	32.50%
20	पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग	100.00%	98.15%	40.68%
21	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	86.95%	89.41%	41.98%
22	औषध विभाग	100.00%	99.46%	43.24%
23	डाक विभाग	100.00%	100.00%	43.42%
24	लोक उद्यम विभाग	100.00%	100.00%	13.51%
25	ग्रामीण विकास विभाग	99.09%	99.95%	43.71%
26	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	100.00%	99.96%	38.13%
27	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	100.00%	100.00%	1.66%
28	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	100.00%	100.00%	54.63%
29	दूरसंचार विभाग	89.23%	85.57%	47.64%
30	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	100.00%	99.96%	45.87%
31	डीएफएस - वित्त मंत्रालय	100.00%	94.54%	37.05%
32	डीएचआर विभाग - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	93.66%	89.71%	33.63%

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	% सक्रिय ई-फाइलें	% ई-रिसीट	>4 औसत विशिष्ट स्तर वाली फ़ाइलों का %
33	दीपम - वित्त मंत्रालय	100.00%	100.00%	38.89%
34	व्यय विभाग - वित्त मंत्रालय	88.93%	62.36%	27.98%
35	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	98.56%	93.57%	43.09%
36	राजभाषा विभाग - वित्त मंत्रालय	94.83%	85.12%	27.33%
37	विधायी विभाग	100.00%	83.92%	32.58%
38	आयुष मंत्रालय	94.12%	79.14%	58.60%
39	नागर विमानन मंत्रालय	98.52%	99.90%	53.23%
40	कोयला मंत्रालय	100.00%	100.00%	36.65%
41	सहकारिता मंत्रालय	100.00%	92.40%	21.90%
42	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	100.00%	100.00%	26.67%
43	संस्कृति मंत्रालय	97.74%	97.21%	44.25%
44	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	100.00%	99.77%	32.79%
45	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	100.00%	100.00%	53.73%
46	शिक्षा मंत्रालय	97.07%	98.51%	40.80%
47	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	98.95%	95.72%	46.20%
48	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	99.91%	99.94%	40.16%
49	विदेश मंत्रालय	99.71%	99.86%	27.74%
50	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	100.00%	93.65%	39.71%
51	भारी उद्योग मंत्रालय	100.00%	99.95%	36.63%
52	गृह मंत्रालय	69.27%	81.48%	28.66%
53	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	99.69%	96.88%	45.86%
54	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	92.92%	74.94%	50.35%
55	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	98.99%	90.13%	50.43%

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	% सक्रिय ई-फाइलें	% ई-रिसीट	>4 औसत विशिष्ट स्तर वाली फ़ाइलों का %
56	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	99.46%	87.03%	42.58%
57	खान मंत्रालय	100.00%	99.97%	43.48%
58	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	100.00%	85.43%	53.25%
59	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	100.00%	99.97%	36.61%
60	पंचायती राज मंत्रालय	100.00%	100.00%	40.19%
61	संसदीय कार्य मंत्रालय	100.00%	100.00%	33.33%
62	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	99.64%	98.89%	34.27%
63	पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	99.20%	99.97%	39.18%
64	विद्युत मंत्रालय	98.42%	99.97%	45.83%
65	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	100.00%	99.90%	40.87%
66	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	99.42%	93.00%	29.93%
67	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	99.88%	99.92%	34.54%
68	इस्पात मंत्रालय	94.24%	98.57%	35.33%
69	वस्त्र मंत्रालय	99.60%	84.20%	38.60%
70	पर्यटन मंत्रालय	100.00%	100.00%	46.91%
71	जनजातीय कार्य मंत्रालय	100.00%	99.28%	33.33%
72	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	100.00%	99.96%	45.41%
73	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	98.69%	99.98%	36%
74	नीति आयोग	100.00%	97.94%	35.36%

ऐसे मंत्रालय/विभाग जिनका औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर 5 से अधिक है, वे डिलेयरिंग/डेलिगेशन की समीक्षा करेंगे।

6 विशेष अभियान और स्वच्छता को संस्थागत करना

संचयी उपलब्धियाँ (2021 – मई 2025)

मापदंड	वि.अ. 1.0 - वि.अ. 4.0	दिसम्बर'24-अप्रैल'25	मई 25	संचयी
अर्जित राजस्व (करोड़ रुपए में)	2364.05	515.08	284.84	**3163.97**
खाली हुआ स्थान (लाख वर्ग फीट में)	643.82	32.43	3.5	**679.75**
स्वच्छता अभियान स्थल	1149935	30889	8835	**1189659**
छाँटी गई फाइलें (लाखों में)	131.4	4.54	0.66	**136.6**

डेटा, प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने और मंत्रालयों/विभागों में स्वच्छता को बढ़ावा देने में विशेष अभियान (**SC1.0-SC4.0**) और सचिवालय सुधारों की निरंतर गति को दर्शाता है। मई 2025 तक, संचयी उपलब्धियों में स्क्रैप निपटान के माध्यम से प्राप्त **₹3163.97 करोड़, 679.75 लाख वर्ग फुट** कार्यालय स्थान खाली होना, स्वच्छता अभियानों के तहत **11.89 लाख से अधिक साइटों को कवर करना और 136.6 लाख फाइलों का निपटान** शामिल है। दिसंबर 2024 से मई 2025 के महीनों में लगातार प्रगति, स्वच्छता के संस्थागतकरण और दैनिक शासन में दक्षता-उन्मुख परिपाटियों की पुष्टि करती है।

6.1. कुल अर्जित राजस्व (करोड़ रुपए में)

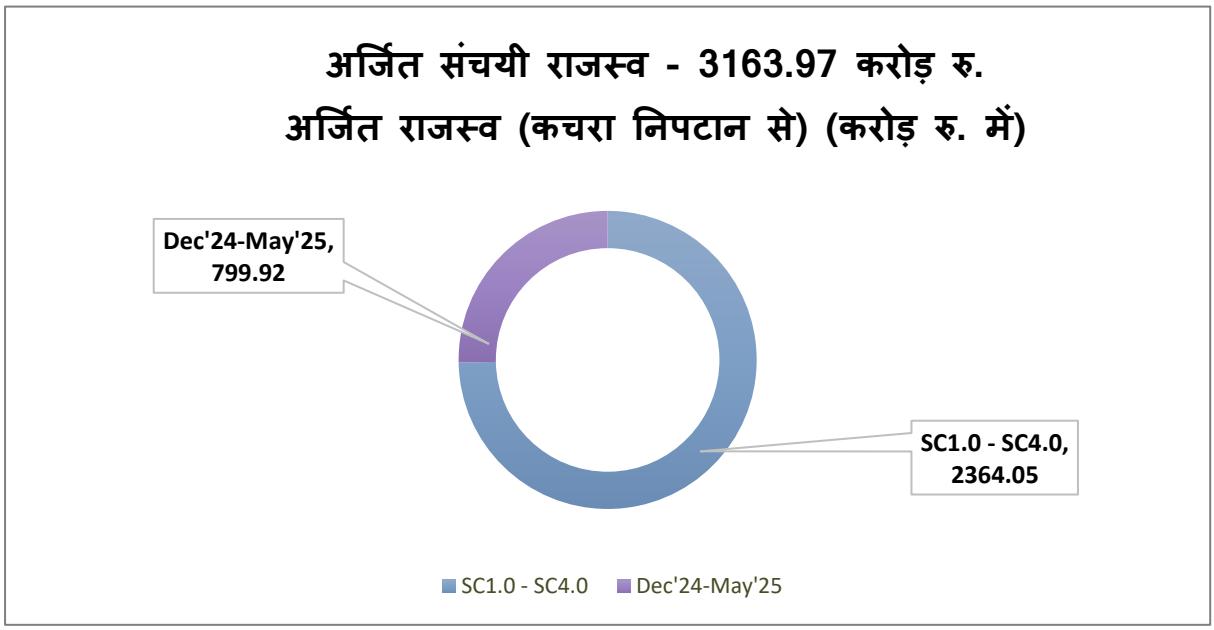

स्क्रैप निपटान के माध्यम से अर्जित कुल **₹3163.97 करोड़ राजस्व में से, ₹799.92 करोड़ केवल दिसंबर'24-मई'25** के दौरान प्राप्त हुए , जो विशेष अभियान **वि.अ. 1.0- वि.अ. 4.0** से आगे निरंतर प्रगति को दर्शाता है , जिसने पहले **₹2364.05 करोड़ का योगदान दिया था**।

6.2. स्क्रैप निपटान से अर्जित राजस्व (मई 2025)

अकेले **रेल मंत्रालय** ने **₹264.87 करोड़ से अधिक का योगदान दिया,** जो इस अवधि के दौरान अर्जित कुल स्क्रैप निपटान राजस्व का लगभग **93% है। इसके बाद MoPSW , MHI, कोयला, MoP और अन्य का स्थान है, जो परिसंपत्ति मुद्रीकरण को आगे बढ़ाने में रेलवे की** महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है ।

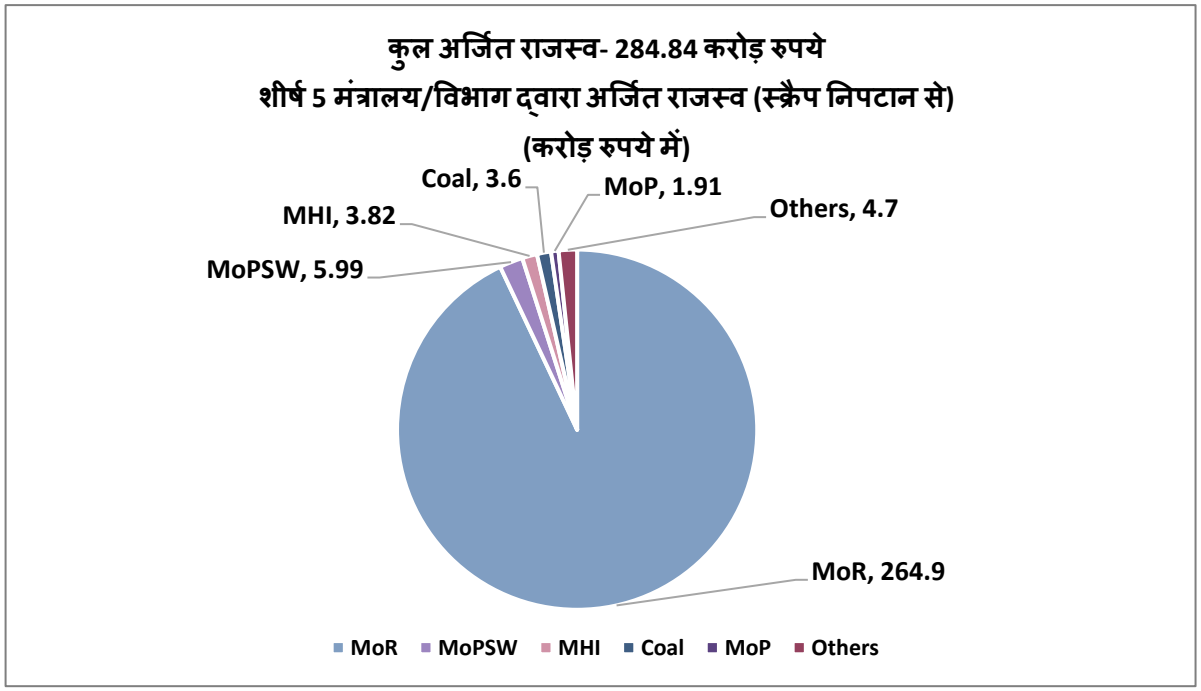

6.3. खाली हुआ स्थान (मई 2025)

खाली हुआ स्थान में, रेल मंत्रालय **(1,30,180 वर्ग फीट)** सबसे आगे है, उसके बाद कोयला मंत्रालय **(76,231 वर्ग फीट) का स्थान** है। एमएचआई, एमएचए और डीएआरई ने सामूहिक रूप से 52,000 वर्ग फीट से अधिक का योगदान दिया, जबकि अन्य विभागों ने 87,269 वर्ग फीट स्थान खाली किया, जो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में व्यापक स्तर पर भागीदारी को दर्शाता है।

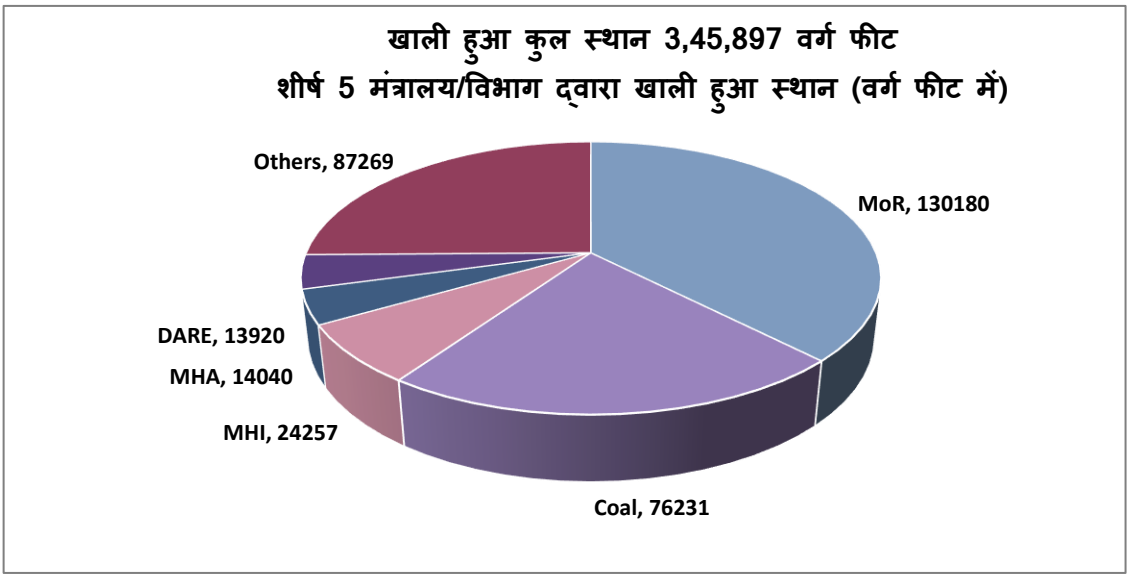

क. शीर्ष 3 मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्क्रैप निपटान के माध्यम से अर्जित राजस्व

- **रेल मंत्रालय**: मई 2025 में अर्जित कुल राजस्व 2,64,87,81,449 रुपये है। अर्जित राजस्व के अनुसार शीर्ष 3 क्षेत्र हैं: -

क्र.सं.	क्षेत्र	अर्जित राजस्व (रु. में)
1.	दक्षिण मध्य रेलवे	1,53,12,90,170
2.	पश्चिमी रेलवे	71,65,00,000
3.	पूर्वी रेलवे	34,00,00,000

- **पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय**: मई 2025 में कुल अर्जित राजस्व 5,98,84,310 रुपये है। अर्जित राजस्व के अनुसार शीर्ष 3 साइटें हैं: -

क्र.सं.	साइट/कार्यालय	अर्जित राजस्व (रु. में)
1.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह	5,22,00,000
2.	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	54,03,300
3.	न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी	15,81,495

- **भारी उद्योग मंत्रालय**: मई, 2025 में कुल अर्जित राजस्व 3,82,20,477 रुपये है। अर्जित राजस्व के अनुसार शीर्ष 3 साइटें हैं: -

क्र.सं.	साइट/संगठन	अर्जित राजस्व (रु. में)
1.	भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	2,72,07,664
2.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	55,78,859
3.	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	29,38,670

6.4. स्वच्छता अभियान साइट (मई 2025)

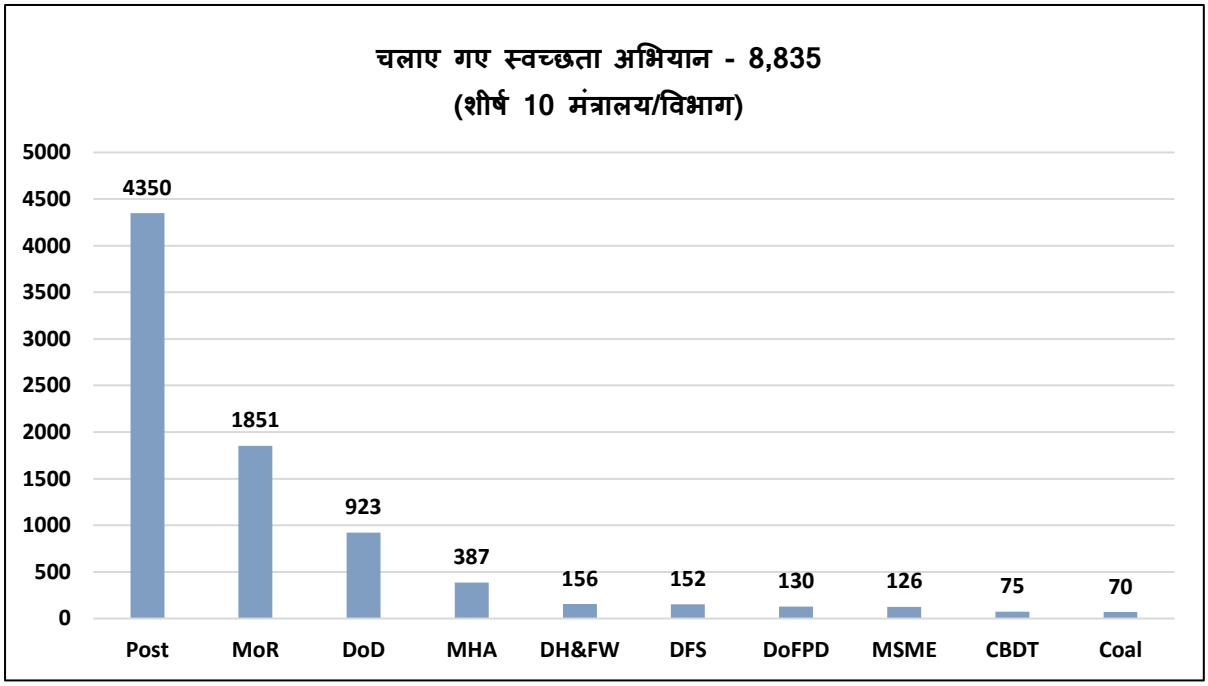

8,835 स्वच्छता अभियानों में से **अकेले डाक विभाग ने लगभग 50% अभियान चलाए** , जिसके बाद रेल मंत्रालय और रक्षा विभाग का स्थान रहा - जो इन विभागों द्वारा स्वच्छता पहलों में मजबूत और निरंतर भागीदारी को दर्शाता है।

6.5. छाँटी गई फिजिकल फाइलें (मई 2025)

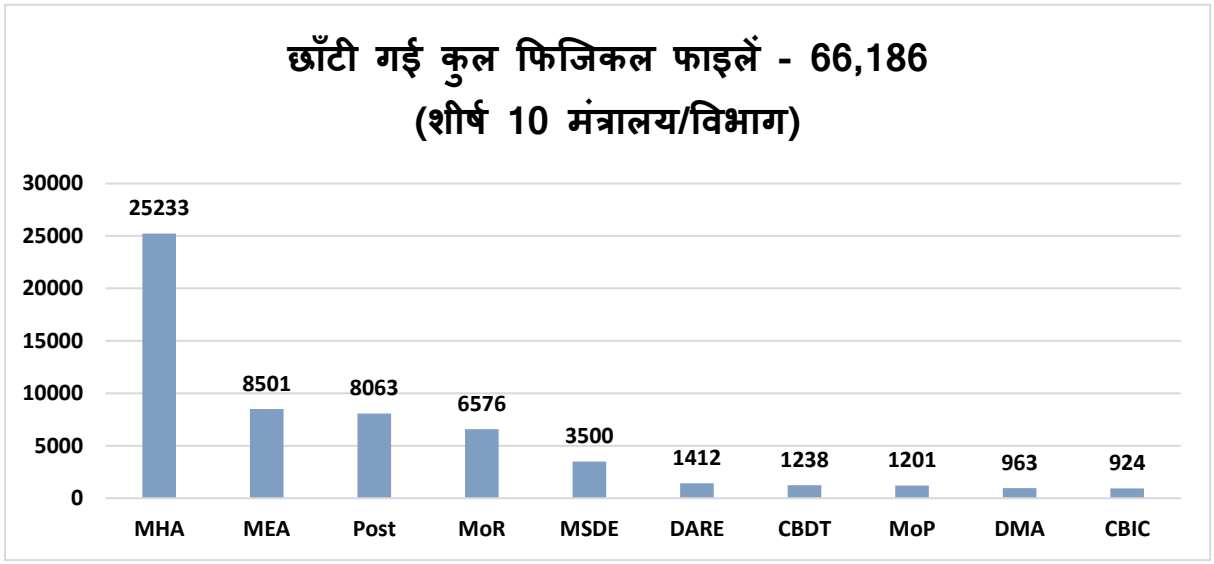

66,186 फिजिकल फाइलों में से गृह मंत्रालय ने 25,000 से अधिक फाइलों को छाँटकर पहला स्थान प्राप्त किया, उसके बाद विदेश मंत्रालय और डाक विभाग का स्थान रहा। यह दर्शाता है कि प्रमुख मंत्रालयों द्वारा अव्यवस्था को दूर करने और फिजिकल फाइल प्रबंधन में सुधार करने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया गया है।

7 पहले - बाद में

मंत्रालयों/विभागों द्वारा एससीडीपीएम पोर्टल पर अपलोड किए गए चित्रात्मक साक्ष्य – मई 2025

पहले

बाद में

अपशिष्ट निपटान - अपशिष्ट प्रबंधन, सुलभ कार्यालय स्थान के माध्यम से सौंदर्य और उपयोगिता को बढ़ाना: **आयकर कार्यालय,कानपूर,उत्तर प्रदेश(पश्चिम);सीबीडीटी**।

पहले

बाद में

बढ़ी हुई उपयोगिता के लिए अव्यवस्था को दूर करना और गहन सफाई करना - **सीबी स्टोर, रानीखेत** में एक परिवर्तित स्थान; **डीओडी**

पहले

बाद में

अखिल भारतीय वाक एवं श्रवण संस्थान (एआईआईएसएच), मैसूर में निपटान के माध्यम से कार्यालय स्थान का संवर्धन; **डीएचएंडएफडब्ल्यू**

8 श्रेष्ठ परिपाटियां ई-कचरा निपटान

एएमडी मुख्यालय, हैदराबाद में ई-कचरे का निपटान किया गया; **डीएई**

भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी में ई-कचरा निपटान किया गया; **एमएसडीई**

9 मंत्रालयों/विभागों का मापदंड - वार कार्य निष्पादन

एमपी संदर्भ

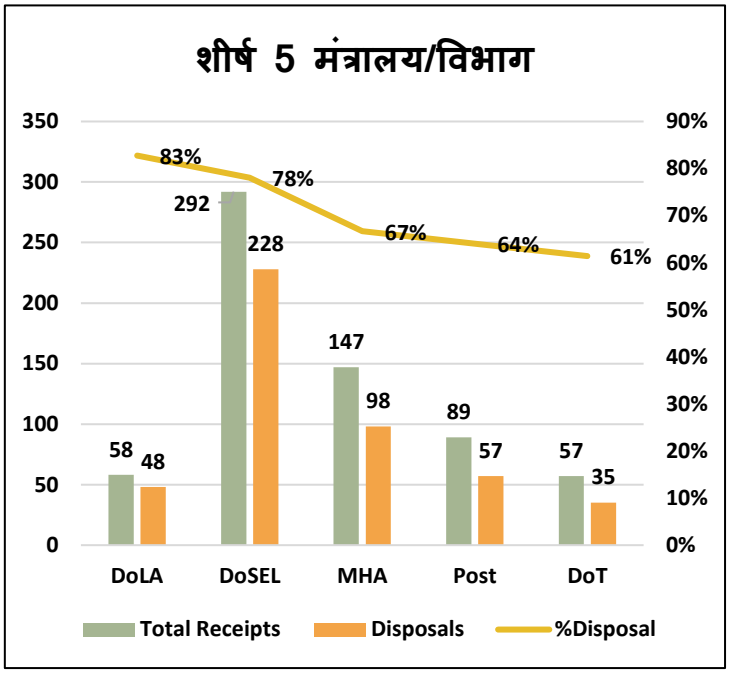

संसदीय आश्वासन

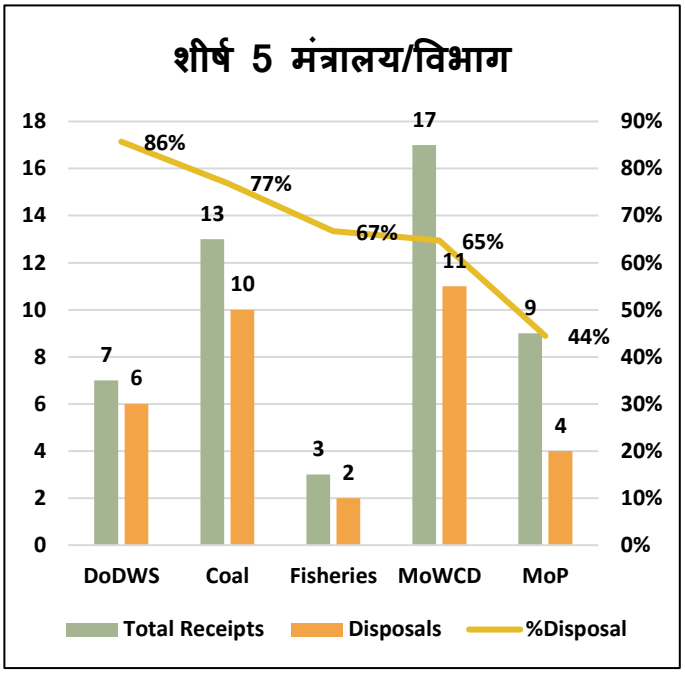

आईएमसी संदर्भ

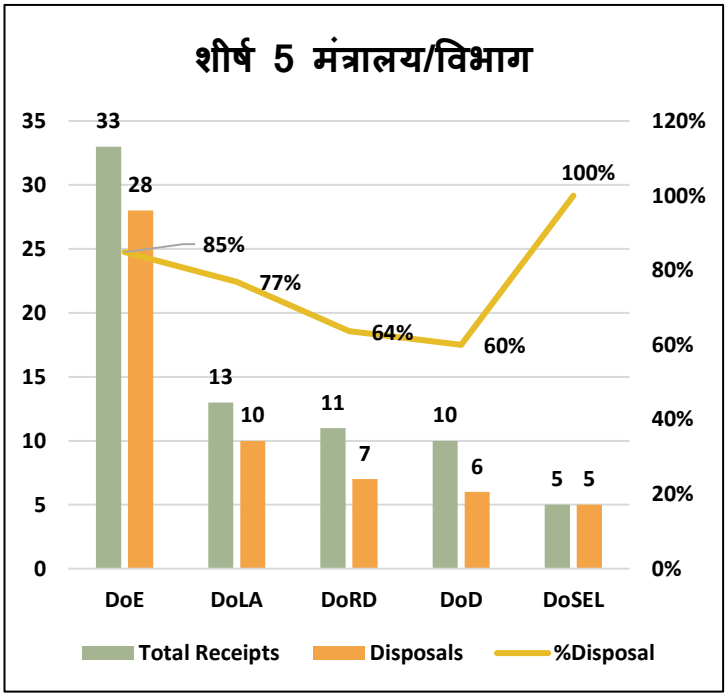

राज्य सरकार संदर्भ

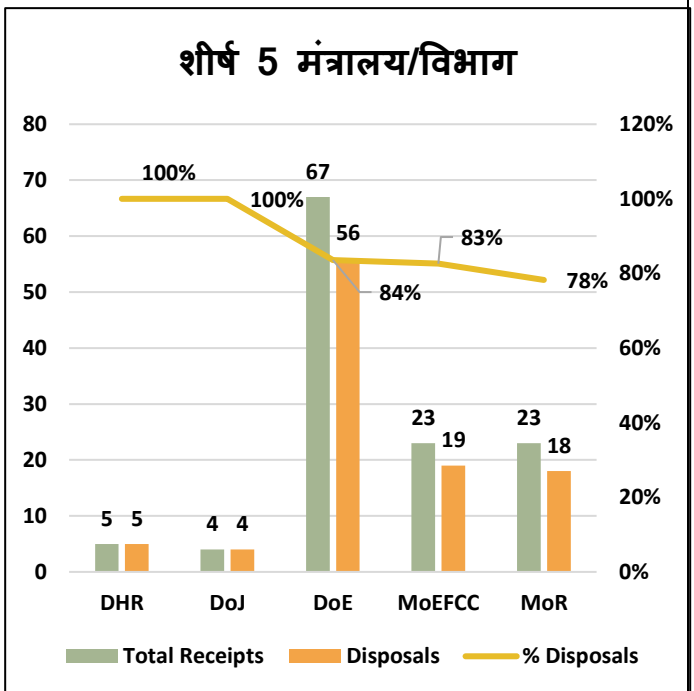

पीएमओ संदर्भ

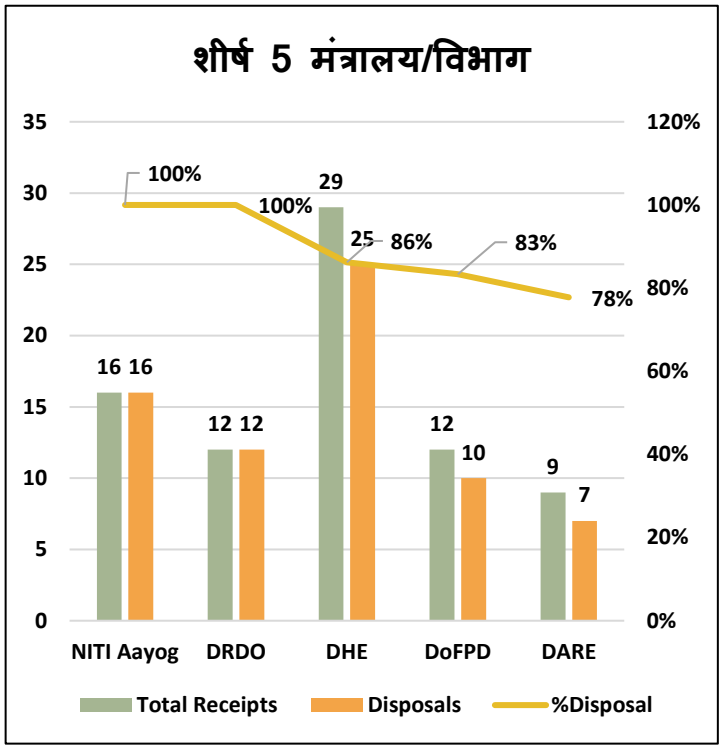

लोक शिकायतें

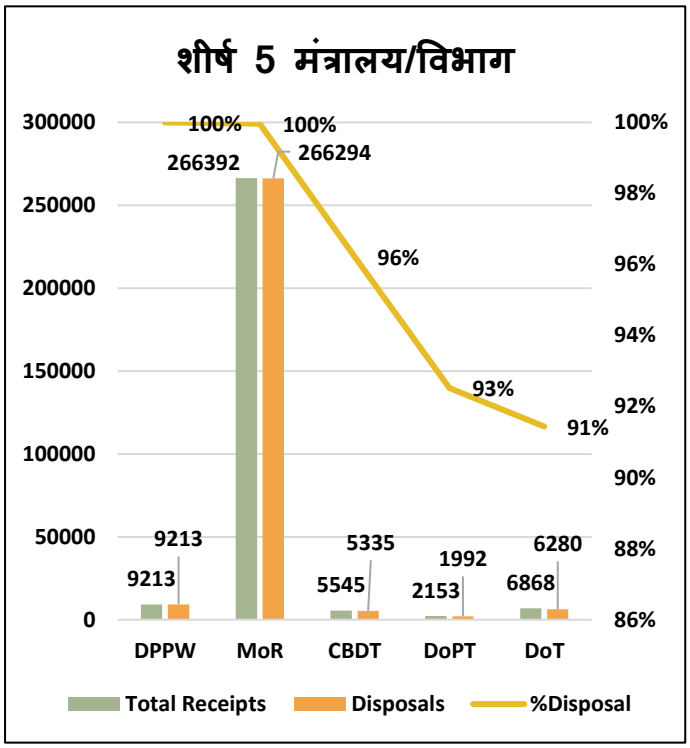

छंटाई की गई फाइलें

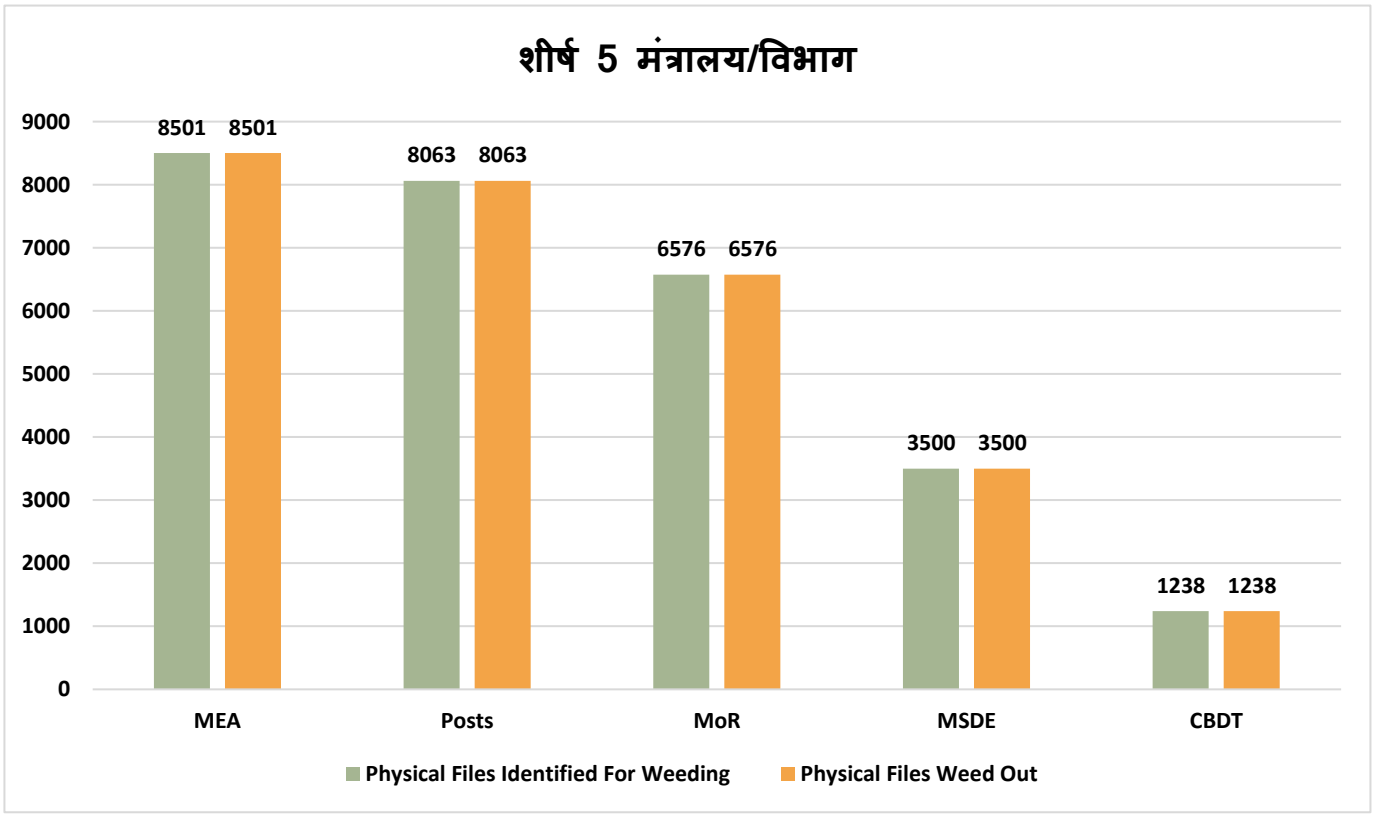

10 इन फोकस: कोयला मंत्रालय

क. परिचय

कोयला मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य अत्याधुनिक और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को अपनाकर कोयला उत्पादन में वृद्धि करना; सिद्ध कोयला संसाधनों को बढ़ाने पर जोर देते हुए अन्वेषण प्रयासों को बढ़ाना तथा पर्यावरण के अनुकूल और संधारणीय तरीके से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए कोयले की शीघ्र निकासी के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास करना है।

विशेष अभियान के तहत कोयला मंत्रालय की उपलब्धियां (अक्टूबर 2021- मई 2025):

- **2.57 करोड़ वर्ग फीट** स्थान को साफ किया गया ।
- **55,021 मीट्रिक टन स्क्रैप निपटान से 300.89 करोड़ रुपए का** राजस्व प्राप्त हुआ ।
- **17,155 फिजिकल फाइलें** छाँटी गईं तथा **68,268 ई-फाइलें** बंद कर दी गईं।
- **स्वच्छता रैलियां, नुक्कड़ नाटक** और सफाई कर्मचारियों के लिए **स्वास्थ्य जांच** जैसी सार्वजनिक सहभागिता गतिविधियां आयोजित की गईं।

ख. झलक

स्वच्छता

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) द्वारा इंदिरा विहार अस्पताल, बिलासपुर के स्क्रैप के निपटान से बनाई गई अमृत फार्मेसी; **कोयला मंत्रालय**।

स्थान का कुशल प्रबंधन

अप्रयुक्त स्थान को रिकॉर्ड रूम, **कोयला भवन, बीसीसीएल, धनबाद, झारखंड** में परिवर्तित किया गया: **कोयला मंत्रालय**

कार्यालय स्थल का संवर्धन

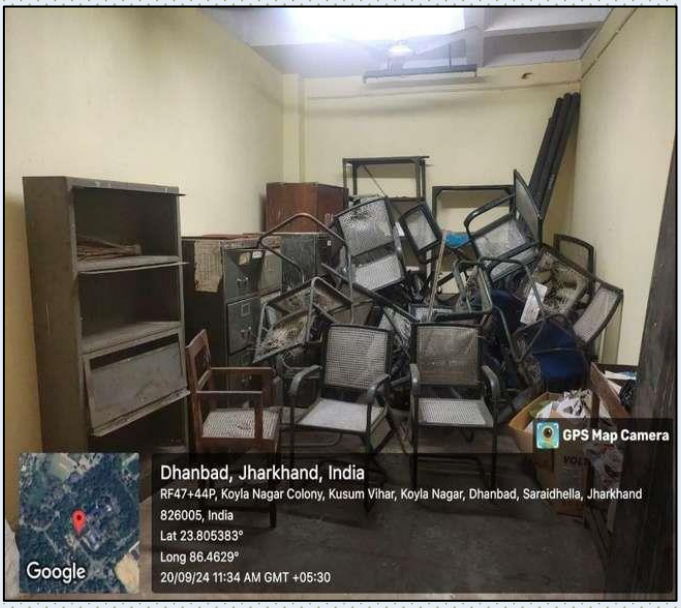

सीएमपीडीआई, धनबाद, झारखंड में स्क्रैप को साफ करके कार्यालय स्थान बनाया गया; **कोयला मंत्रालय**

कार्यालय स्थल का संवर्धन

अप्रयुक्त स्थान को **बीसीसीएल कार्यालय, धनबाद** में टेबल टेनिस रूम में परिवर्तित किया गया; **कोयला मंत्रालय**

अपशिष्ट से धन

कचरे को कलाकृति के उल्लेखनीय टुकड़े में बदलना **एनएलसीआईएल (कोयला का पीएसयू), रफी मार्ग जंक्शन, नई दिल्ली** द्वारा कचरे से बनाया गया, जय हिंद चक्र; **कोयला मंत्रालय**

स्क्रैप को कलाकृति के रचनात्मक टुकड़े में बदलना, एक अप्रयुक्त राजदूत कार को फिर से इस्तेमाल करना **सीसीएल (कोयला मंत्रालय का पीएसयू), रांची, झारखंड; कोयला मंत्रालय**

स्क्रैप को पहचान के प्रतीक में बदलना, स्क्रैप धातु शीट और इंजन फ्लाईव्हील को इन-हाउस वेल्ड करके सीसीएल लोगो बनाना, **सीसीएल (कोयला मंत्रालय का पीएसयू), रांची, झारखंड; कोयला मंत्रालय**

स्क्रैप को उपयोगी और आनंददायक बनाना, पुरानी लोहे की पाइपों, बेकार बेल्टों, चेनों, फ्रेमों और अन्य स्क्रैप सामग्रियों को खेल के उपकरण, बेंचों और कुर्सियों में बदलना; **एससीसीएल (कोयला मंत्रालय का सार्वजनिक उपक्रम), तेलंगाना; कोयला मंत्रालय**

स्क्रैप को ट्रिब्यूट टू नॉलेज में बदलते हुए, एनएलसीआईएल (कोयला मंत्रालय का सार्वजनिक उपक्रम) ने लोहे के स्क्रैप से तैयार की गई एक खनिक की किताब पढ़ते हुए मूर्ति स्थापित की, **नेवेली माइंस, एनएलसीआईएल तमिलनाडु; कोयला मंत्रालय**

11. निर्णयन में दक्षता वृद्धि पर कार्यालय ज्ञापन

डॉ. टी.वी. सोमनाथन
Dr. T.V. Somanathan

मंत्रिमंडल सचिव
भारत सरकार
CABINET SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

D.O. No. 502/2/2/2021-CA.V

27th November, 2024

Dear Secretary,

As you are aware, many initiatives have been undertaken in the recent years to make governance more responsive, accountable and transparent. The initiative for Increasing Efficiency in Decision Making, implemented since 2021, is a step in the same direction. It aims at achieving flatter and leaner organizational structures by putting in place appropriate delegation at various levels, rationalizing workload, thereby speeding up decision-making while increasing the productivity and efficiency of officers.

2. These measures have been incorporated into the Central Secretariat Manual of Office Procedure, 2022 wherein, it is emphasized that, each Ministry/Department will review the instructions on levels of disposal and channel of submission, keeping the number of levels to the minimum by delegating powers to lower formations. To facilitate quicker decision-making, the channels of submission should not be more than four.

3. However, it is observed that delayering is not being implemented in true spirit and a trend of increasing the channels of submission is observed in some Ministries/Departments. This is against the essence of the reforms undertaken so far and creates potential delays in file processing.

4. To sustain the measures undertaken as a part of Increasing Efficiency in Decision Making, you are advised to review the levels of disposal and channel of submission in your Ministry/Department and ensure that the levels do not exceed four and that the Special Secretary/ Additional Secretary/ Joint Secretary function independently as bureau heads.

5. I request you to devote your personal attention to this matter and ensure that these measures are implemented in letter and spirit, thereby fostering speedy and efficient decision making in Government.

With best wishes,

Yours sincerely,

(T.V. Somanathan)

To,

All Secretaries to Government of India

Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhavan, New Delhi-110004
Tel.: 011-23016696, 23011241 Fax : 011-23018638 E-mail : cabinetsy@nic.in

12. स्वच्छता को संस्थागत करने पर कार्यालय ज्ञापन

No. Q-150122/2024-O&M-DARPG (8885)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Administrative Reforms & Public Grievances

Sardar Patel Bhawan, New Delhi
Dated 17th December 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Continuation of campaign for Swachhata and Reducing pending matters to the Minimum Possible in Government.

It has been decided that as a sequel to the month-long Special Campaign 4.0 for Swachhata and disposal of pending matters conducted from 2nd October 2024 to 31st October 2024, the campaign has to be institutionalized and the thrust of the campaign should be maintained throughout the year. Accordingly, the following actions may be taken up by Ministries/Departments on a regular basis in order to keep the pendency to minimum possible:

(i) The system of Special Campaign Portal and Nodal Officers will continue to be operational to oversee the institutionalization / continuation of activities covered in the Special campaign.

(ii) All Ministries/Departments may dedicate 3 hours every week for continuation of activities covered in the Special campaign across all offices of Ministries/ Departments.

(iii) Nodal Officers of each Ministry may review the progress of activities on a weekly basis and the Secretary of the Ministry/ Department may review the progress on a monthly basis.

(V. Srinivas)
Secretary to the Government of India

To

All Secretaries of the Government of India

Copy for information to:
1. Principal Secretary to the PM
2. Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi (Ms. Kavita Singh, JS)
3. All Nodal Officers of Special Campaign 4.0

Copy to:
Senior Technical Director, NIC, DARPG

12. स्वच्छता को संस्थागत करने पर कार्यालय ज्ञापन

No. Q-15012/2/2024-O&M-DARPG (e-8885)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Administrative Reforms & Public Grievances

Sardar Patel Bhawan, New Delhi
Dated 31st December, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Continuation of campaign for Swachhata and Reducing pending matters to the Minimum Possible in Government.

****

In continuation of this Department's Office Memorandum of even No. dated 17.12.2024 (copy enclosed) on the above subject it is informed that the monthly data may be reported by the Nodal Officers on the SCDPM Portal i.e. https://scdpm.nic.in. Nodal Officers can access the SCDPM portal from 3rd January, 2025 and data entry may be completed by 7th of every month.

Encl: As above.

(V. Srinivas)
Secretary to the Government of India

To

All Secretaries of the Government of India

Copy for information to:

1. All Nodal Officers of Special Campaign 4.0
2. Senior Technical Director, DARPG, NIC.

02/01/25

13. ई ऑफिस पर कार्यालय ज्ञापन

MOST IMPORTANT

No.O-16012/6/2017-ARC-DARPG (e2938)
Government of India
Ministry of Personnel, Pensions and Public Grievances
Department of Administrative Reforms & Public Grievances

6th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan,
Janpath, New Delhi
Dated 17th January, 2025

OFFICE MEMORANDUM

Subject: eOffice Analytics - regarding.

*****

The undersigned is directed to say that the following guidelines may be adopted by Ministries / Departments for implementation of eOffice in Central Secretariat:

(i) Display their standing orders of delayering/Channels of Submission on their respective e-Office dashboard.

(ii) Review Virtual Private Network (VPN) usage. Non-users may be identified and steps may be taken to deactivate / close the idle account after due examination and process. The NIC teams of Ministries/Departments may approach NIC VPN Division to obtain VPN data and for deactivation of idle VPN accounts.

(iii) Follow the Manual of Office Procedure strictly and to avoid proliferation of part-files on the same subject. 'Common office function codes' as prescribed in Chapter - 6 'File Management System' of CSMOP 2022 are to be followed at the time of opening a new eFile in eOffice.

(iv) Use of Knowledge Management System (KMS) for managing the OM's Circulars, Orders etc. and further adding them as references in eFiles. Further, a list of all files (Division-wise/bureau-wise), in PDF, may be placed in the KMS for reference of all so as to avoid creation of multiple files in the same Head or part files.

(v) Review the Designation Master in Personal Information Management System (PIMS) and identify the designations related to Personal Staff of officers. Based on the list of designations received from the Ministries / Departments, personal staff of officers will be removed from the counts of

13. ई ऑफिस पर कार्यालय ज्ञापन

(vii) Review the Basic File Head and notify the standardized Heads based on the relevant subjects of the Ministry/Department. Based on the list of Heads received from the Ministries/Departments, a consolidated list of Heads will be prepared which may be considered as standard Subjects to fetch the Subject-wise pendency.

(viii) The Ministries/Departments who process statutory clearance for various projects such as Ministry of Environment, Forest and Climate Change may provide expected time for clearance, so that the processing time of such files may be noticed.

(ix) E-Office Analytics to be developed to indicate file pendency at each level, to identify time delays and pendency. Emphasis to be given to identifying subject specific pendency across Ministries/Departments.

2. This issues with the approval of Secretary, DARPG.

सुनील सिंह

(Sunil K. Singh)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. No.011-23440371
email: sunilk singh73@nic.in

To

Secretaries to the Govt. of India

Copy to:

1. DG, NIC
2. Shri M.K. Mishra, DDG, NIC email: mk.mishra@nic.in
3. Shri Kapil Kumar Sharma, Sr. Director (IT), NIC
4. eOffice-PMU, NIC

Copy for information to:

PSO to Secy. (AR&PG)/PA to JS (SC) /DS (eOffice)

अनुलग्नक I : अपलोड न किए गए आंकड़े

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग
1.	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
2.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग
3.	राजभाषा विभाग
4.	लोक उद्यम विभाग
5.	युवा कार्यक्रम विभाग
6.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
7.	जनजातीय कार्य मंत्रालय

अनुलग्नक II- संक्षिप्ताक्षरों की सूची

क्र. सं.	संक्षेपाक्षर	मंत्रालय/विभाग का नाम
1.	सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आय कर)
2.	सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
3.	डीपीआईआईटी	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
4.	डीएआरपीजी	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
5.	डीएआरई	कृषि अनुसंधान एवं किसान विभाग
6.	डीए एंड एफडब्ल्यू	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
7.	डीएएच	पशुपालन, डेयरी विभाग
8.	डीएई	परमाणु ऊर्जा विभाग
9.	डीबीटी	बायोटेक्नोलॉजी विभाग
10.	डीसीपी	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग
11।	डीओसी	वाणिज्य विभाग
12.	डीओसीए	उपभोक्ता मामले विभाग
13.	डीओडी	रक्षा विभाग
14.	डीओडीपी	रक्षा उत्पादन विभाग
15.	डीआरडीओ	रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग
16.	एमओ डोनर	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
17.	डीईए	आर्थिक कार्य विभाग
18.	डीईपीडब्ल्यूडी	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
19.	डीईएक्सडब्ल्यू	भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
20.	डीओई	व्यय विभाग
21.	डीओएफ	उर्वरक विभाग
22.	डीएफएस	वित्तीय सेवा विभाग
23.	फिशरीज	मत्स्य पालन विभाग

क्र. सं.	संक्षेपाक्षर	मंत्रालय/विभाग का नाम
24.	डीओएफपीडी	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
25.	डीएच एंड एफडब्ल्यू	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
26.	डीएचआर	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
27.	डीएचई	उच्चतर शिक्षा विभाग
28.	दीपम	विनिवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
29.	डीओजे	न्याय विभाग
30.	डीओएलआर	भूमि संसाधन विभाग
31.	डीओएलए	विधि कार्य विभाग
32.	डीएमए	सैन्य कार्य विभाग
33.	डीओएल	राजभाषा विभाग
34.	डीपीपीडब्ल्यू	पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
35.	डीओपीटी	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
36.	डीओपीएच	औषध विभाग
37.	पोस्ट्स	डाक विभाग
38.	डीओपीई	लोक उद्यम विभाग
39.	डीओआर	राजस्व विभाग
40.	डीओआरडी	ग्रामीण विकास विभाग
41.	डीओएसईएल	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
42.	डीएसटी	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
43.	डीएसआईआर	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
44.	डीओएसजेई	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
45.	डीओएस	अंतरिक्ष विभाग
46.	स्पोर्ट्स	खेल विभाग
47.	डीओटी	दूरसंचार विभाग
48.	डीओडब्ल्यूआर एंड आरडी	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

क्र. सं.	संक्षेपाक्षर	मंत्रालय/विभाग का नाम
49.	डीओवाईए	युवा कार्यक्रम विभाग
50.	एलडी	विधायी विभाग
51.	आयुष	आयुष मंत्रालय
52.	मोका	नागर विमानन मंत्रालय
53.	कोल	कोयला मंत्रालय
54.	को-ऑपरेशन	सहकारिता मंत्रालय
55.	एमसीए	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
56.	एमओसी	संस्कृति मंत्रालय
57.	एमओडीडब्ल्यूएस	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
58.	एमओई	शिक्षा मंत्रालय
59.	एमओईएस	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
60.	माइटी	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
61.	एमओईएफसीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
62.	एमईए	विदेश मंत्रालय
63.	एमओएफ	वित्त मंत्रालय
64.	एमओएफपीआई	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
65.	एमएचआई	भारी उद्योग मंत्रालय
66.	एमओएचएफडब्ल्यू	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
67.	एमएचए	गृह मंत्रालय
68.	एमओएचयूए	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
69.	एमआईबी	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
70.	एमओएलई	श्रम और रोजगार मंत्रालय
71.	एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
72.	एमओएम	खान मंत्रालय
73.	एमओएएमए	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

क्र. सं.	संक्षेपाक्षर	मंत्रालय/विभाग का नाम
74.	एमएनआरई	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
75.	एमओपीआर	पंचायती राज मंत्रालय
76.	एमपीए	संसदीय कार्य मंत्रालय
77.	एमओपीएनजी	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
78.	एमओपी	विद्युत मंत्रालय
79.	एमओआर	रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
80.	एमओआरटीएच	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
81.	एमओपीएसडब्ल्यू	पतन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय
82.	एमएसडीई	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
83.	एमओएसपीआई	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
84.	एमओएस	इस्पात मंत्रालय
85.	एमओटी	वस्त्र मंत्रालय
86.	टूरिज़्म	पर्यटन मंत्रालय
87.	एमओटीए	जनजातीय कार्य मंत्रालय
88.	एमओडब्ल्यूसीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
89.	एमओवाईएएस	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
90.	नीति आयोग	नीति आयोग

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

भारत सरकार

सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली - **110001**